

पश्चिमी सेती वदियुत परियोजना: नेपाल

प्रलिस के लयि:

भारत-नेपाल संबंध, भारत-नेपाल शांति और मतिरता संध 1950, पश्चिमी सेती जलवदियुत परियोजना ।

मेन्स के लयि:

भारत-नेपाल संबंध और महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

चीन लगभग छः वर्षों तक (2012 से 2018 तक) पश्चिमी सेती जलवदियुत परियोजना में शामिल रहा । वर्ष 2018 में चीन के बाहर होने के लगभग चार वर्षों के बाद भारत द्वारा इस परियोजना का अधगिरहण कया जाएगा ।

- इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लुंबिनी का दौरा कया गया, जहाँ उन्होंने 2566वीं बुद्ध जयंती समारोह मनाया गया । नेपाल ने भी भारत को पश्चिमी सेती जलवदियुत परियोजना में नविश करने के लयि आमंत्रति कया है ।

प्रमुख बदि

पश्चिमी सेती वदियुत परियोजना:

- यह प्रस्तावति 750 मेगावाट की जलवदियुत परियोजना है, जसि सुदूर-पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है । जो पछिले छह दशकों से इसका सरिफ खाका ही नरिमति हो है ।
- हाल ही में सरकार ने 1,200 मेगावाट वदियुत उत्पादन करने की क्षमता वाली एक संयुक्त भंडारण परियोजना, वेस्ट सेती और सेती नदी (SR-6) परियोजना को फरि से तैयार कया है ।
- इसके भंडारण या जलाशय मानसून के मौसम के दौरान भर जाएगा और इनसे शुष्क मौसम में प्रत्येक दनि पीक आवर्स के दौरान वदियुत की उत्पादन करने के लयि पानी निकाला जाएगा ।
- इसकी सफलता से नेपाल में भारत की छवि को बहाल करने और जलवदियुत परियोजनाओं के लयि भवषिय के वचारों में इसे महत्त्व देने की उम्मीद है, ऐसे समय में जब प्रतसिपर्धा कठनि हो । इसलयि, पश्चिमी सेती में भवषिय में नेपाल-भारत के शक्ति संबंधों के लयि एक परभाषति मॉडल बनने की क्षमता है ।



भारत-नेपाल ऊर्जा संबंध:

- नेपाल लगभग 6,000 नदियों और 83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ वदियुत् स्रोतों में समृद्ध है।
- 6,480 मेगावाट उत्पादन के लिये वर्ष 1996 में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे, लेकिन भारत अभी भी वसितृत परियोजना रिपोर्ट के साथ सामने नहीं आ पाया है।
- **ऊपरी करनाली परियोजना**, जिसके लिये बहुराष्ट्रीय GMR ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं, ने वर्षों से कोई प्रगति नहीं की है।
- पूर्वी नेपाल की संखुवा सभा में 900 मेगावाट की अरुण-3 परियोजना को क्रयिन्वति करने में भारत ने सफलता हासिल की, जिसकी नींव वर्ष 2018 में रखी गई थी और जिसे वर्ष 2023 तक पूरा करने के लिये निर्धारित किया गया है, ने हाल ही में भारत में वशिवास बनाने में मदद की है।
- वर्ष 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी परियोजनाओं को समय पर नषिपादति करना शुरू करना चाहिये।
- नेपाल के संवधान में एक प्रावधान है जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों पर किसी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या समझौते के लिये कम से कम दो-तह्राई बहुमत से संसद के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह भी होगा कि किसी भी हाइड्रो परियोजना पर हस्ताक्षर करने और नषिपादन के लिये दिये जाने से पहले शासकीय कार्यों की आवश्यकता होगी।
- नेपाल में बजिली की भारी कमी है क्योंकि यह लगभग 2,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के मुकाबले केवल लगभग 900 मेगावाट उत्पादति करता है। हालाँकि यह वर्तमान में भारत को 364 मेगावाट बजिली नरियात कर रहा है, लेकिन पछिले कुछ वर्षों में यह भारत से आयात कर रहा है।

भारत-नेपाल राजनयिक संबंध:

- नेपाल और भारत के बीच गतरिध के कारण 2015 में आर्थिक प्रतर्बिध आरोपित किया गया लेकिन **ओली के बाद नए पीएम देउबा के पदभार संभालने के बाद समीकरण बदल गए**, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, जहाँ उन्होंने भारत के साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करने का फैसला किया।
- नेपाल भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे **भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी वदिश नीति में विशेष महत्त्व रखता है।**
- भारत और नेपाल वर्तमान नेपाल में स्थिति **बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी** के साथ **हिंदू धर्म** और **बौद्ध धर्म** के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं।
- दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की नरिबाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनषिठ संबंध हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से रोटी-बेटी के रशिते के रूप में जाना जाता है।
- **1950 की शांति और मतिरता की भारत-नेपाल संधि** भारत एवं नेपाल के बीच मौजूद वशिष संबंधों का आधार है।
- नेपाल में उत्पन्न होने वाली नदियों पारस्थितिकी और जलवदियुत् क्षमता के साथ ही भारत की **बारहमासी नदी परणालियों** को पोषित करती हैं।
- हालाँकि नवंबर 2019 में **सीमा मुद्दा** तब उभरा जब नेपाल ने एक नया राजनीतिक नकशा जारी किया था, जिसमें नेपाल के क्षेत्र के हसिसे के रूप में उत्तराखंड के कालापानी, लमिपथिधुरा और लपुलेख का दावा किया गया था। नए नकशे में सुस्ता (पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार) के क्षेत्र को भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

आगे की राह

- जब तक भारत नेपाल के जल को महत्त्व देने के लिये सहमत नहीं हो जाता है और बजिली पर मौजूदा फोकस की समीक्षा नहीं की जाती है, तब तक आपसी अवशिवास लंबे समय में दोनों पक्षों की प्रगति की क्षमता को प्रभावित करता रहेगा।

- एक बार जब परियोजनाओं को बहुउद्देश्यीय बना दिया जाता है तो - बाढ़ नियंत्रण, नेविगेशन, मत्स्य पालन, कृषि विकास में योगदान देने वाली सचिाई आदि के साथ पानी को उचित मूल्य प्राप्त होगा एवं बजिली की लागत मौजूदा दरों की तुलना में बहुत कम होगी और दोनों पक्षों के लोगों को एकाधिक लाभ होगा ।
- बजिली व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिये जिससे भारत नेपाल में विश्वास पैदा कर सके । भारत में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ होने के बावजूद जलविद्युत ही एकमात्र स्रोत है जो भारत में चरम मांग का प्रबंधन कर सकता है ।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/west-seti-power-project-nepal>

